वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबन्ध) अधिनियम 1985 के अंतर्गत रुग्ण कंपनियों का जिलेवार ब्यौरा संकलित नहीं किया जाता है। औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड ने सूचित किया है कि 31 दिसम्बर, 1988 की स्थिति के अनुसार रुग्ण, औद्योगिक कंपनी विशेष उपबन्ध) अधिनियम, 1985 की धारा 15 के अंतर्गत राजस्थान में फैक्टरी (फैक्टरियों) वाली औद्योगिक कंपनियों से संबंधित 30 मामले दर्ज किए गए थे।

(ख) रुग्ण औद्योगिक एककों को पुनरूज्जीवित करने के लिए अपेक्षित उपाय अधिनियम, की धारा 18(1) में दिये गये है।

राजस्थान में ग्रामीण बैंकों की शाखाएं

3522. **श्री सन्तोष बागड़ोदिया** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राजस्थान में ग्रामीण बैंकों की कुल कितनी शाखायें काम कर रही हैं ;

(ख) क्या सरकार राज्य में इस प्रकार के बैंकों की नई शाखायें खोलने का विचार रखती है ; और

(ग) यदि हां, तो भीलवाड़ा जिले में इस प्रकार की कितनी शाखायें और किन-किन स्थानों पर खोलने का विचार है ?

वित्त मंत्रालय में आर्थिक कार्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री एडुवर्डो फेलेरियो) : (क) से (ग) भारतीय रिजर्व बैंक ने सूचित किया है कि दिसम्बर, 1988 के अन्त में राजस्थान में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की 1034 शाखायें कार्य कर रही थी। वर्ष 1985–90 की वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति के अन्तर्गत, भारतीय रिजर्व बैंक ने राजस्थान में शाखायें खोलने के वास्ते क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को 120 ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी केन्द्र आवंटित किये हैं। भारतीय रिजर्व बैंक ने आगे बताया है कि भीलवाड़ा जिले में कम बैंक सुविधाओं वाला ऐसा कोई खंड नहीं है जहां वर्तमान शाखा लाइसेंसिंग नीति में निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के लिये अतिरिक्त बैंक कार्यालय खोलने की आवश्यकता हो।

रायपुर, मध्य प्रदेश में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना

3523. **श्री अजीत जोगी** : क्या **विधि और न्याय** मंत्री राज्य सभा में क्रमशः 10 नवम्बर, 1986 और 26 नवम्बर, 1987 को तारांकित प्रश्न 99 और तारांकित प्रश्न 297 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बतायेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने जसवंत सिंह आयोग की सिफारिशों के अनुसार रायपुर में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के खंडपीठ की स्थापना करने के प्रस्ताव के संबंध में मध्य प्रदेश सरकार की टिप्पणियां और विचार प्राप्त किये हैं ;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) रायपुर में उच्च न्यायालय की खंडपीठ की स्थापना करने के संबंध में अंतिम निर्णय कब तक ले लिया जायेगा ?

विधि और न्याय मंत्री तथा जल संसाधन मंत्री (श्री बी० शंकरानन्द) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Agitation by Bodos in Assam

3524. SHRI CHITTA BASU:

SHRI DEBA PRASAD RAY:

Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Bodo Adivasis' agitation in Assam has taken a seri-

ous turn and many lethal arms and weapons have been recently recovered from the possession of those agitators;

(b) whether many persons have been killed|injured and also properties have been destroyed as a result of the agitation; if so, what are the details thereof;

(c) whether a political solution of this problem is being initiated by the Central Government; and

(d) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI SANTOSH MOHAN DEV): (a) Yes, Sir.

(b) According to available information there have been 62 deaths, 71 cases of attacks on police|forest officers, 34 cases of bomb explosion, 50 cases of burning of Bridges and 98 cases of Arson from 16th February, 1989.

(c) and (d) While the Central Government are not in favour of further division of Assam, they believe that the genuine grievances of the tribal people of Assam should be attended to promptly and with sympathy and that a conscious effort should be made to create a sense of participation among them. The State Government have been advised accordingly. They were also advised to initiate meaningful dialogue with the tribals.

Self Employment Programme

3525. SHRI H. HANUMANTHAPPA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) what is the number of persons assisted as on 1st January, 1989 under Self Employment Programme;

(b) what is the number of applications received under this scheme during the last three years and the number of those who have actually been financed; and

(c) whether Government propose to continue the scheme?

THE MINISTER OF STATE IN THE DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) Under the Scheme for providing Self Employment to Educated Unemployed Youth (SEEUY), a total number of 1029109 persons have been sanctioned loans up to the end of 1987-88.

(b) The physical targets, number of applications received in the District Industries Centres, number of applications sponsored to banks and number of applications sanctioned by the banks during the last three years are indicated below:

(No. in lakhs)

Financial year	Physical targets	No. of applications received in DICs	No. of applications sponsored to banks	No. of applications sanctioned by banks
1985-86	2.50	8.58	3.42	2.21
1986-87	2.50	9.10	3.31	2.17
1987-88	1.25	6.80	2.08	1.20

(c) The scheme will continue during the the remaining period of the Seventh Five Year Plan.